THE

PARLIAMENTARY DEBATES

OFFICIAL REPORT

IN THE HUNDRED AND TWENTY-FIFTH SESSION OF THE RAJYA SABHA

Commencing on the 18th February, 1983/29 Magha, 1904 (Saka)

RAJYA SABHA

Friday, the 18*th February,* 1983/ 29 *Magha,* 1904 (*Saka*)

The House met at twenty minutes past twelve of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

PRESIDENT'S ADDRESS

SECRETARY-GENERAL: Sir, I beg to lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the President's Address to both the Houses of Parliament assembled together on the 18th February, 1983.

[*Text of the President's Address in Hindi*]

माननीय सदस्यगण, वर्ष 1983 में, संसद् के इस पहले अधिवेशन में, मैं आपका स्वागत करता हूं। आने वाला वर्ष हमारे लिए चुनौतियों और अवसरों से भरा हुआ है, जिसके लिए संसद्, सरकार और जनता को मिल-जुल कर काम करना होगा।

2. आर्थिक मोर्चे पर, आवश्यकता इस बात की है कि अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाया जाए, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जाए, अनुत्पादक खर्च को खत्म किया जाए और कीमतों पर काबू रखा जाए। कई देशों में मुद्रा फैलाव के बावजूद, हम मुद्रा के फैलाव पर नियन्त्रण रखने में सफल रहे हैं, जिस पर हमारा गर्व करना वाजिब है। वर्ष 1983 की मध्य जनवरी में थोक-बाजार कीमतें इससे पहले के 12 महीनों की अपेक्षा केवल 2.8 प्रतिशत ही अधिक रहीं। और यह सब उस व्यापक सूखे के बावजूद है, जिसकी लपेट में 4.8 करोड़ हैक्टेयर भूमि आ गई थी और 31.2 करोड़ लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया और उसे अधिक कुशल बनाया गया। पिछले तीन वर्षों में लगभग 50,000 उचित दर की दुकानें खोली गई। इस वर्ष केन्द्रीय सरकार सूखा, बाढ़ और तूफान के शिकार लोगों को राहत देने के लिए राज्यों को लगभग 700 करोड़ रुपये की राशि देगी, जो राहत कार्य के लिए किसी भी वर्ष मे दी जाने वाली राशि से ज्यादा है। इन कुदरती आफतों के शिकार लोगों से हमें हमदर्दी है और हम उनके साहस और राहत कार्यों में लगे कार्यकर्त्ताओं की कर्त्तव्य-निष्ठा की सराहना करते हैं।

3. हमारे बुनियादी ढांचे और हमारे उद्योग ने विकास की गति को बनाए रखा है। अप्रैल 1983 और दिसम्बर 1982 के बीच, बिजली के उत्पादन में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कोयले

का उत्पादन 4.2 प्रतिशत बढ़ा तथा सीमेंट का उत्पादन 10.2 प्रतिशत और फर्टिलाइजर का उत्पादन 9.6 प्रतिशत बढ़ा है। रेल गाड़ियों द्वारा माल की ढुलाई 3.5 प्रतिशत बढ़ी है। बन्दरगाहों में, जहाजों को माल उतारने के लिए जो काफी समय तक इन्तजार करना पड़ता था, वह अब लगभग खत्म हो गया है। इस्पात के उत्पादन मे फिर से बढ़ोतरी हुई है। तेल की ऊंची कीमतें अर्थ-व्यवस्था पर बोझ बनी रहीं, परन्तु इस अरसे के दौरान देश में कच्चे तेल का उत्पादन 30.6 प्रतिशत बढा है। जहां 1980-81 मे, कच्चे तेल का उत्पादन 1.05 करोड़ मीटरी टन था, वहां 1981-82 में यह उत्पादन 1.62 करोड़ मीटरी टन हो गयी और अनुमान है कि 1982-83 में यह उत्पादन बढ़ कर 2.1 करोड़ मीटरी टन हो जाएगा। भुगतान-शेष की कठिनाइयों, मौसम की प्रतिकूल स्थितियों और साधनों की भारी कमी के बावजूद, अर्थ-व्यवस्था में लगातार दूसरे वर्ष भी उचित विकास हुआ है। चालू वर्ष के पहले 9 महीनों में सार्वजनिक क्षेत्र की कुल टर्न ओवर 21 प्रतिशत बढ़ी है। लघु उद्योग क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है और इसने लगभग 10 प्रतिशत के विकास की दर को बनाए रखा है। खरीफ और रबी की फसलों के सामने आई समस्याओ के बावजूद, चावल और गेहूं की वसूली इससे पहले के किसी भी वर्ष की अपेक्षा अधिक रही। सरकार ने किसानों को वसूली की ऊंची कीमतें दी है।

4. निर्यात मे वृद्धि को कायम रखा जा रहा है। पिछले वर्ष के पहले सात महीनों की अवधि में, निर्यात के अनन्तिम आंकड़े 3,960 करोड़ रुपये थे, जबकि चालू वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान निर्यात उससे लगभग 17.8 प्रतिशत अधिक होने की आशा है। आयात में तीव्र वृद्धि की प्रवृति को रोक दिया गया है। हालांकि हमारी अर्थ-व्यवस्था की विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए कुल आयात खर्च में कुछ वृद्धि दिखाई पड़ सकती है, फिर भी, तेल की खोज में तेजी से काम करने के कार्यक्रम और इस्पात तथा फर्टिलाइजर्स जैसे अन्य क्षेत्रों में अधिक उत्पादन और पूंजी लगाए जाने से, आयात में और आगे वृद्धि पर काबू रखना सम्भव हो सकेगा। विकासशील देश जिस कच्चे माल का निर्यात करते हैं, उसकी कीमतों मे तेजी से गिरावट आई है, परन्तु जिस तैयार माल को हम आयात करते है उनकी कीमतें काफी बढ़ गई है। पश्चिमी देशों में ब्याज की ऊंची दरों ने भारत जैसे देशों के लिए स्थिति को और भी गम्भीर बना दिया है।

5. संसार एक गम्भीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। बहुत से देश मंदी की लपेट में हैं और वे इन्वेस्टमेंट में कटौती करते रहे हैं। फिर भी हमने अपनी विकास की गति को बनाए रखा है। केन्द्रीय योजना खर्च 27 प्रतिशत बढ़ गया है और केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं को मिला कर उन पर कुल खर्च 21 प्रतिशत बढ़ गया है। 14 जनवरी, 1982 को घोषित संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम के, जिसमें निर्धन और कमजोर वर्ग के लोगों की भलाई पर बल दिया गया है, उत्साहजनक नतीजे निकले हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन इस वर्ष 33 करोड से अधिक अतिरिक्त श्रम-दिवसों का देहाती रोजगार पैदा किया जाएगा। खादी और ग्राम उद्योग कमीशन के कार्यकलापों में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और सक्रिय रूप से इस बात के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि इनका सम्बन्ध ग्रामीण रोजगार के लिए की जा रही सभी कोशिशों के साथ जोड़ दिया जाए। पीने के पानी की सुविधा ऐसे और 24,000

गांवों में पहुंचाई गई जहां पीने के पानी की समस्या थी । 5 लाख 40 हजार मकान बनाने के लिए जगह दी गई है। आवास और शहरी विकास निगम 2 लाख 25 हजार घर बनाने के लिए सहायता देगा । इस वर्ष 23.5 लाख हैक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा जुटाई जा रही है ।

6. जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई है, राष्ट्र उनका कृतज्ञ है । उनके प्रति आभार के प्रतीक के रूप में सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना में विस्तार किया है ।

7. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह प्रयत्नशील है और इसके लिए उसने त्रिमुखी नीति तैयार की है । इसमें राज्यों की विशेष कम्पोनेन्ट योजनाओं, और अनुसूचित जाति विकास निगमों के अलावा राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों की विशेष कम्पोनेन्ट योजनाएं, और विशेष केन्द्रीय सहायता भी शामिल हैं। जनजातीय उप-योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता को वर्ष 1982-83 में 85 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 95 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

8. हमारे समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और पिछड़ी श्रेणियों के लोगों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति की दिशा में किए जा रहे कार्य को सरकार के विकास कार्यक्रमों मे प्राथमिकता दी जाती रहेगी । केन्द्र द्वारा आयोजित मछियारों की एक बीमा योजना भी शुरू की गई है ।

9. परिवार नियोजन कार्यक्रमों में लोगों के भाग लेने और उसके आम समर्थन की एक लहर पैदा हुई । अप्रेल 1982 से जानकारी 1983 की अवधि के दौरान परिवार नियोजन के सभी तरीकों को स्वीकार करने वालों की संख्या इससे पहले की इसी अवधि की संख्या से 16% अधिक थी । संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन कुष्ट रोग, नेत्रहीनता और तपेदिक पर नियंत्रण के कार्यक्रमों को एक नये जोश के साथ लागू किया जा रहा है ।

10. औद्योगिक कर्मचारियों के लिए हमें उतनी ही चिन्ता है जितनी कि कृषि मजदूरों और किसानों के लिए है। औद्योगिक विवाद एक्ट में जो संशोधन किए गए हैं उनमें शिकायतों को निपटाने के लिए एक अंदरूनी मशीनरी की व्यवस्था है और उनमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि श्रम- न्यायालय एक निर्धारित समय में ही अपना निर्णय दे दें ।

11. शिक्षा के स्तर में सुधार लाने, बालिगों में निरक्षरता समाप्त करने और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने के कार्यक्रमों और नीतियों को जिसमें बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, उच्च प्राथमिकता दी जाती रही है।

12. पिछले वर्ष की दो महत्वपूर्ण घटनाएं रही, जिनका हमारे नौजवानों के भविष्य पर और उनकी शारीरिक तथा मानसिक स्फूर्ति पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा । ये घटनायें हैं—खेल विभाग की स्थापना और सफलता के साथ एशियाई खेलों का आयोजन । जिस ढंग से इन खेलों का आयोजन किया गया, उसकी व्यापक सराहना हुई है । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मुताबिक खेलकूद सुविधाओं के जुटाए जाने और 17 स्टेडियमों के निर्माण एवं दर्जा बढ़ाये जाने ने यह सिद्ध कर दिया है कि हम बड़े पैमाने पर खेलों को आयोजित करने की क्षमता रखते हैं । खेलकूद का

यह बुनियादी ढांचा आने वाले वर्षों में हमारे पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों के काम आता रहेगा।

13. एशियाई खेलों के कारण हमें बहुत से नए क्षेत्रों में दूरदर्शन का विस्तार करने और रंगीन प्रसारण का "प्रारंभ" करने का अवसर भी मिला है। हमारी दूरदर्शन नीति में देहाती लोगों की जरूरतों, और शिक्षा तथा विकास के लिये इस शक्तिशाली माध्यम के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

14. विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हमारे लिये यह एक घटनापूर्ण वर्ष रहा है। हमने टेक्नोलॉजी संबंधी अपना नीति वक्तव्य तैयार किया है और उसकी घोषणा कर दी है, जिसमें उन बातों को निर्धारित किया गया है जो देसी टेक्नोलॉजी के विकास और ऐसी टेक्नोलॉजी के आयात के संबंध में निर्णय लेने में हमारा मार्ग दर्शन करेंगी, जिससे हम शक्तिशाली हों। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में अपना कार्य जारी रखेंगे। हम मूल विज्ञान के साथ-साथ Bio-Technology, Immunology, Nuclear Science में Fast Breeder Technology और समुद्र इंजिनियरी जैसे नए क्षेत्रों की ओर ध्यान दे रहे हैं। दक्षिणी ध्रुव में अब हमारा दूसरा वैज्ञानिक अभियान चल रहा है जिसमे महत्वपूर्ण प्रयोग किये जा रहे हैं और भविष्य में एक ऐसा स्थायी केन्द्र कायम करने के लिये स्थान का सर्वे किया जा रहा है जहां आदमी रह कर काम कर सकें। सागर-तल में Poly-Metalic Nodules के सर्वे के हमारे कार्य को सागर-नियमसम्मेलन में Pioneer Investor के रूप में मान्यता मिली है। भारत ही एक मात्र ऐसा विकासशील देश है जिसे इस प्रकार की मान्यता हासिल हुई है।

15. इस वर्ष INSAT-1B छोड़ा जाएगा जो ऊंचे दर्जे की दूर-संचार, दूरदर्शन और मौसम विज्ञान संबंधी क्षमता हासिल करने में हमारी सहायता करेगा। INSAT-1A के छोड़े जाने से जिसका मूल डिजाइन ठीक था, जो अनुभव हमें हासिल हुआ उसे ध्यान में रखते हुए INSAT-1B में आवश्यक संशोधन किये जायेंगे।

16. माननीय सदस्यगण उन समस्याओं से वाकिफ हैं जो तारापुर Nuclear Power Reactor के लिये ईंधन की पूर्ति को निश्चित रूप में बरकरार रखने में हमारे सामने आई हैं। इन्हें अब फ्रांस और अमरीका की सरकारों के साथ सलाह-मशवरे से हल कर लिया गया है।

17. अब मै देश की अंदरूनी राजनीतिक स्थिति की ओर आता हूं। फूट डालने वाली और विघटनकारी ताकतें हिंसा भड़काने और राष्ट्रीय ढांचे को कमजोर करने में लगी हुई हैं। इनका मुकाबला दृढ़ता के साथ किया जाना चाहिये। असम और पंजाब जैसे मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श में विरोधी दलों को शामिल करने के लिये सरकार ने पहल की है और यह सराहनीय प्रवृत्ति जारी रहनी चाहिये। बहुत से क्षेत्रों में साम्प्रदायिक और राष्ट्रविरोधी तत्व आपत्तिजनक गतिविधियों में लगे हुए हैं। इनको कारगर ढंग से दबाना होगा। उत्तर-पूर्वी कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उग्रवादी संगठन सरगर्म हैं। इनकी गतिविधियों से निपटने तथा शांति और सामान्य स्थिति बनाये रखने के लिये हमने अच्छे तालमेल के साथ एक अभियान चलाया है। इसी बीच पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विकास कार्यों की गति को बढ़ाया गया है।

18. हाल में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा और संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली में और इससे पहले हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं। मेघालय में चुनाव अभी-अभी समाप्त हुए है और असम में चुनाव चल रहे हैं। ये चुनाव हमारी लोकतांत्रिक परम्परा का हिस्सा और एक संवैधानिक जिम्मेदारी रहे हैं।

19. अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बिगड़ गई है। तटवर्ती देशों की इच्छाओं का अनादर करते हुए हिन्द महासागर में विदेशी सैनिकों का बढ़ता हुआ अनाधिकार प्रवेश, ईरान और इराक के बीच लगातार युद्ध, इजराइल का बढ़ता हुआ दुःसाहस और फिलिस्तिनियों की मुसीबतें, दक्षिण अफ्रीका की जातिवादी सरकार की अपनी ही जनता और अपने पड़ोसी देशों के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाइयां तथा निरस्त्रीकरण की बातचीत, और उत्तर-दक्षिण वार्ता में गतिरोध—ये सब चिंताजनक मामले हैं। दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व एशिया के हालात के राजनीतिक हल अभी निकाले जाने बाकी हैं।

20. पड़ोसी देशों में होने वाली कुछ-एक गतिविधियों से हमारी सुरक्षा का वातावरण बिगड़ा है। हमारे पड़ोसी देश, पाकिस्तान द्वारा सोफिस्टिकेटेड हथियार हासिल किये जाने से सारा राष्ट्र चिन्तित है। हमारी अपनी नीति पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने और इस दिशा में पहल करने की रही है। उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ और दोनों देशों के अधिकारियों के बीच जो बैठकें हुई हैं, उनसे अंततः शांति, दोस्ती और सहयोग के स्थायी संबंधों का रास्ता तैयार होगा।

21. बंगलादेश के मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक के साथ भी हमारी बातचीत हुई है। इससे हमारे दोस्ती के संबंध और मजबूत हुए हैं। चीन के साथ सीमा के सवाल तथा दोनों देशों के अन्य आपसी मसलों पर सरकारी-स्तर की बातचीत का तीसरा दौर पिछले महीने बीजिंग में हुआ था। भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ हमारे अच्छे संबंध बने रहे हैं।

22. सारे संसार में तथा अपने क्षेत्र में शांति, सहनशीलता और स्थिरता बनाये रखने के लिये गुटनिरपेक्षता की हमारी नीति से हमें बिना विचलित हुए काम करने में सहायता मिली है। जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते हैं अगले महीने के शुरू में दिल्ली में गुटनिरपेक्ष देशों का सातवां सम्मेलन हो रहा है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा सर्वसम्मति से अनुरोध किये जाने पर हम इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। हमारे देश में होने वाला राष्ट्राध्यक्षों का यह सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। हम यह आशा करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने जो समस्यायें हैं उनका हल निकालने में यह शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण योगदान देगा। बाद में इसी वर्ष नई दिल्ली में एक और मुख्य सम्मेलन हो रहा है, यह है राष्ट्रमंडल देशों की सरकारों के अध्यक्षों की बैठक। इन दोनों सम्मेलनों को सफल बनाने के लिये हमें अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिये।

23. मैं अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति द्वारा की गई आस्ट्रेलिया तथा युगोस्लाविया और श्रीमती प्रधान मंत्री की ब्रिटेन, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, मारीशस, मोजाम्बिक और सोवियत संघ की यात्राओं का भी जिक्र करना चाहूंगा तथा साथ ही तंजानिया और ग्रीस के राष्ट्रपतियों, भूटान नरेश, मोजाम्बिक

अल्जीरिया, नौरु, पाकिस्तान, फ़्रांस, मिश्र और नाईजीरिया के राष्ट्रपतियों, ब्रिटेन, नेपाल और मारीशस के प्रधान मंत्रियों, फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे के अध्यक्ष, बंगला-देश के मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक तथा दूसरे राजनेताओं द्वारा की गई भारत की यात्राओं का भी उल्लेख करूंगा। यात्राओं के इस आदान-प्रदान से आपसी लाभ हुआ है।

24. माननीय सदस्यगण, संसार में आर्थिक और राजनैतिक संकटों के कारण जो तनाव बढ़ा है उसका मुकाबला भारत केवल चौकसी, एकता और अपनी उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग द्वारा ही कर सकता है। भ्रष्टाचार और अकुशलता से जूझने के अलावा, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मतभेदों को इस तरह प्रकट न किया जाये जिससे हिंसा भड़के या हमारी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो। पिछले तीन वर्षों में हम अपनी स्थिरता और प्रगति को बरकरार रख सके हैं। मेरा हार्दिक अनुरोध है कि समस्त राष्ट्र भारत, की अखंडता को बनाये रखने और उसके कल्याण तथा सम्मान को बढ़ाने के लिये मिलकर काम करे।

25. मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि उनके सामने जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें सहयोग और सद्भावना से पूरा करे। बजट कार्य, विधायी कार्य तथा अन्य कार्य जो आपके सामने है उन्हें सफलता के साथ पूरा करने के लिये मैं आपको अपनी शुभकामनाएं पेश करता हूं। जय हिन्द

[Text of the President's Address in English]

Honourable Members, I welcome you to the first session of Parliament in 1983. The year ahead is full of challenges and opportunities, which will require the united efforts of Parliament, Government, and the people.

2. On the economic side, the need is to tone up the economy, enhance production and productivity, eliminate non-productive expenditure and contain prices. In the midst of inflationary pressures in several countries, we can take legitimate pride in our success in containing inflation. Wholesale prices in mid January, 1983 were only 2.8 per cent higher than 12 months earlier. And this in spite of widespread drought affecting 48 Million hectares and 312 million (31.2 crores) people. The public distribution system was expanded and made more efficient. About 50,000 fair price shops were opened in the last three years. This year the Central Government would be releasing to the States about Rs. 7,000 million (Rs. 700 crores), the highest in any year for relief to victims of drought, floods and cyclones. Our sympathies go to the people hit by these natural calamities and we admire their courage and the sense of duty of relief workers.

3. The performance of our infrastructure and our industry has maintained improvement. Between April and December, 1982, power generation rose by 7.2 per cent and production of coal by 4.2 per cent, cement by 10.2 per cent and fertilizers by 9.6 per cent. The railways increased the movement of freight by 3.5 per cent. The ports have, by and large, eliminated the waiting time of vessels. There has been a recovery in steel production. The high prices of oil continued to be a burden on the economy, but domestic production of crude during the period rose by 30.6 per cent. Against 10.5 million (1.05 crores) tonnes in 1980-81, production was 16.2 million (1.62 crores) tonnes in 1981-82 and is anticipated to be 21 million (2.1 crores) tonnes in 1982-83. In spite of the difficulties of balance of payments, unfavourable seasonal conditions, and the severe constraint on resources, the economy

achieved reasonable growth for a second successive year. The turnover of public sector has increased by 21 per cent in the first nine months of the current year. There has been significant expansion in the small industry sector which has maintained a rate of growth of around 10 per cent. Despite the problems faced by kharif and rabi, procurement of rice and wheat was higher than in any previous year. Government have given farmers the benefit of higher procurement prices.

4. The increase in exports is being maintained. In the first seven months of the current financial year exports are expected to be about 17.8 per cent higher than the provisional figure of Rs. 39,600 million (Rs. 3960 crores) in the corresponding period of the previous year. The trend towards rapid increases in imports has been curbed. Although the overall import bill may show a rise to meet the developmental needs of our economy it will be possible to check the growth of imports further with the accelerated programme of oil exploration and production and increased investments in other sectors such as steel and fertilizers. Prices of the raw materials whch developing countries export have fallen sharply, while the prices of manufactured goods which we import have gone up considerably. The high interest rates in the West have further aggravated the situation for countries like India.

5. The world is going through a critical economic period. Many countries are in the grip of recession and have been cutting down investment. We, however, were able to maintain the tempo of our development. Central Plan outlay has increased by 27 per cent and the total outlay on Central and State Plans put together has gone up by 21 per cent. The Revised Twenty-Point Programme, which was announced on 14 January, 1982 with its emphasis on the service of the poor and the weak, has shown heartening results. This year, more than 330 mililon additional mandays of rural employment will be generated under the National Rural Employment Programme. There has also been significant spurt in the activties of the Khadi and Village Industries Commission and efforts have been consciously made to link these with the overall effort towards rural employment. Drinking water facilities have been extended to a further 24,000 problem villages. More than 540,000 house sites have been provided. Loans from the Housing and Urban Development Corporation will help the Construction of 225,000 dwellings. An additional irrigation potential of 2.35 million hectares is being created during the year.

6. As a token of the debt which the nation owes to persons who brought us freedom, the Government have enlarged the Freedom Fighters' Pension Scheme.

7. Government are vitally concerned with the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and have evolved a three-pronged strategy This consists of the Special Component plans of State Governments and Central Ministries, special Central assistance in addition to the States' Special component plans, and the Scheduled Castes Development Corporations. Special Central assistance for tribal sub-plans has been stepped up from Rs. 850 million (Rs. 85 crores) to Rs. 950 million (Rs. 95 crores) for 1982-83.

8. The social and economic advancement of the economically weaker sections and of the backward classes of our society will continue to be given priority in Government's development programmes. A Centrally sponsored scheme of fishermen's insurance has been launched.

9. There was a surge of popular support to and participation in the Family Planning Programmes. During the Period April, 1982 to January, 1983 the number of acceptors of all family planning methods was 16 per cent higher than that for the correspon-

ding period of the previous year. Programmes for the control of leprosy, blindness and tuberculosis are being implemented with renewed vigour under the Revised Twenty-Point Programme.

10. Our concern for industrial workers equals our concern for agricultural workers and farmers. The amendments to the Industrial Disputes Act provide for internal machinery to settle grievances and ensure that labour courts give decisions within a stipulated time.

11. Programmes and stretegies for improving the quality of education, eradicating adult illiteracy and universalising elementary education in the age group of 6—14 continued to receive high priority with special emphasis on the education of girls.

12. Two significant events of last year which will have a far-reaching impact on the future of our young people, and their physical and mental alterness, are the creation of a Department of Sports and the successful holding of Asian Games. The manner in which the Games were organised has been widely acclaimed. The construction and upgradation of 17 stadia and sports facilities conforming to international standards proved our capacity to rise to major challenges. This infrastructure will serve our sportsmen and sportswomen in the years to come.

13. The Games also provided the occasion for the extension of television to many new areas and the introduction of colour telecasting. Our television policy will give special attention to the needs of our rural population and the utilisation of this powerful medium for education and development.

14. It has been an eventful year for our science and technology. We have formulated and announced a Technology Policy Statement setting out the considerations that will guide our decisions in the development of indigenous technology and the import of such technology as will strengthen us. We shall pursue our search for technological self-reliance. We are paying attention to both basic science and to new areas like bio-technology, immunology, fast breeder technology in nuclear science and ocean engineering. Our second scientific expedition is now in Antarctica continuing important experiments and surveying the area for setting up a permanent manned station in future. Our work in the survey of polymetallic nodules on the ocean floor has been rewarded with our recognition, at the Conference of Law of the Sea, as a pioneer investor. We are the only developing country so recognised.

15. INSAT-1B which will be launched this year will help us to attain a high level of telecommunication, television and meteorological capability. It will incorporate the modifications required in the light of our experience with INSAT-1A, the basic design of which was sound.

16. Honourable Members are aware of the problems we faced in ensuring continuity of fuel supplies for our Tarapur nuclear power reactor. These have now been sorted out in consultation with the Governments of France and USA.

17. I shall now turn to the domestic political scene. Divisive and disruptive forces are at work fomenting violence and weakening the national fabric. These must be fought resolutely. Government have taken the initiative to associate the Opposition in discussions on major issues like those relating to Assam and the Punjab, and this welcome trend must continue. Communal and anti-national elements have been indulging in objectionable activities in many areas and these will have to be effectively curbed. Extremist organisations have been active in

certain north-eastern States and territories. We have adopted a well-coordinated drive to combat these activities and maintain peace and normalcy. Meanwhile the tempo of development effort all over the north-eastern region has been stepped up.

18. Elections have recently taken place in Andhra Pradesh, Karnataka, Tripura and the Union Territory of Delhi and in Haryana, Himachal Pradesh, Kerala and West Bengal earlier. Polling has just concluded in Meghalaya and is in progress in Assam. These elections have been part of our democratic tradition and a constitutional obligation.

19. The international situation has deteriorated. The escalation of foreign military intrusion in the Indian Ocean in disregard of the wishes of littoral States, the continuing war between Iran and Iraq, the increasing recklessness of Israel and the sufferings of the Palestinians, the aggressive acts of the racist regime of South Africa against its own people and its neighbours and the lack of progress in the Disarmament Talks and in North-South dialogue are all matters of concern. Political solutions are yet to be found to the situations in South-West and South-East Asia.

20. Certain developments in our neighbourhood have worsened our security environment. The entire nation is exercised over the acquisition of sophisticated weaponry by our neighbour, Pakistan. Our own policy has been to pursue initiatives and improve relations with our neighbours. It is hoped that the meetings that have taken place with the President of Pakistan and between officials of the two countries will eventually lead to the conclusion of an enduring relationship of peace, friendship and cooperation.

21. We have also had talks with the Chief Martial Law Administrator of Bangladesh. These have led to a strengthening of friendly relations. The third round of official-level talks with China on the boundary question and other bilateral matters took place in Beijing last month. Our relations with Bhutan, Nepal, and Sri Lanka have maintained their even course.

22. Our policy of non-aligned has helped us to work unswervingly for the objectives of peace, friendship and stability throughout the world and in our region. As Honourable Members are aware, the Seventh Conference of Non-Aligned Countries will take place early next month in New Delhi. We are playing host to it at the unanimous request of the non-aligned community. It will be the largest gathering of Heads of nations to be held in our country. It is our ardent hope that the summit will make an important contribution to the solution of the problems besetting the international community. Later in the year another major conference is being held in the Capital—the Commonwealth Heads of Government Meeting. We must put all our energies into the task of making a success of both these conferences.

23. I should also refer to the visits of my predecessor to Ireland and Yugoslavia and of our Prime Minister to the United Kingdom, Saudi Arabia, the United States of America, Japan, Mauritius, Mozambique and the Union of Soviet Socialist Republics and the visits of India of the Presidents of Tanzania and Greece, King of Bhutan, the Presidents of Mozambique, Algeria, Nauru, Pakistan, France, Egypt and Nigeria, the Prime Ministers of the United Kingdom, Nepal and Mauritius, the Chairman of the P.L.O., the Chief Martial Law Administrator of Bangladesh as well as other statesmen. These exchanges have been of mutual benefit.

24. Hon. Members, the economic and political crises in the world

have led to a sharpening of tensions which India can withstand only through vigilance, unity and the optimal use of its own productive capacity. Apart from fighting corruption and inefficiency, it must be ensured that differences are not aired in a manner which provokes violence or weakens our secular democratic fabric. In the last three years we have been able to a maintain stability and progress. It is my earnest entreaty that the entire nation will work together to maintain India's integrity and enhance its welfare and good name.

25. I urge Honourable Members to approach the vital tasks before them in a spirit of cooperation and harmony. I wish you all success in the budgetary, legislative and other business that awaits you. JAI HIND.

OBITUARY REFERENCES

MR. CHAIRMAN: I refer with profound sorrow to the passing away of Mr. Leonid Ilyich Brezhnev, President of the U.S.S.R., Acharya Vinoba Bhave, Shri Mahendra Mohan Chaudhury, an ex-Member, Shri Piloo Mody a sitting Member, Shrimati Yashoda Reddy and Shri C. K. Daphtary, ex-Members of this House.

In the death of Mr. Leonid Ilyich Brezhnev, President of the Soviet Union, General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the U.S.S.R., the world has lost an outstanding leader who guided the destiny of not only his country, but the whole world for nearly two decades. He was not the Leader of the Soviet Union alone; he was in a way an important leader of mankind and by virtue of his policies, he influenced the course of history in many ways.

Though leading a super-power country Mr. Brezhnev fully realised the consequences of a third World War and a nuclear holocaust. As such, he untiringly worked for lasting world peace and *detente* and put forward several proposals for limiting nuclear arsenals and strategic arms which culminated in the signing of the Strategic Arms Limitation Treaty with the U.S.A.

For us the passing away of Mr. Brezhnev is loss of a true and steadfast friend who had always shown keen interest in the development and well-being of this country. He had developed a close friendship and established a personal rapport with the Prime Minister Shrimati Indira Gandhi, and in spite of his busy schedule, he vsited this country twice during the last decade. It was under his leadership that the Indo-Soviet Cooperation and Friendship Treaty was signed, and economic trade scientific and cultural exchanges acquired a new dimension and achieved maturity. His death is as much a loss to India as it is to the Soviet Union.

Mr. Brezhnev showed the friendliest interest in our progress and, if I may say so, there had never been the slightest suggestion, implicit or explicit, that we should line up with the Soviet Union on issues having international bearing.

Born in a steel worker's family in 1906, in the Ukraine Province of the Soviet Union, Mr. Leonid Brezhnev joined the Communist Party at the young age of 17. In the early days of his life, he was engaged in land reclamation and agricultural work, but he joined the Institute of Metallurgy in 1935 and qualified from there as an engineer. He soon worked his way up, but during the Second World War was drafted in the Soviet Army. When the War came to an end, he had risen to the rank of Lt.-General. After the War, he was actively engaged in party and State affairs and slowly rose in the party hierar-